

Publication	The Indian Express	Language	English
Edition	New Delhi	Journalist	Bureau
Date	29/03/2025	Page no	10
CCM	25.37		

Govt: Soon, cooperative taxis to take on private aggregators

Govt: Soon, cooperative taxis to take on private aggregators

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, MARCH 28

A TAXI service cooperative akin to private taxi aggregators will be soon launched, the Ministry of Cooperation said in a statement Friday.

The cooperative will be formed by willing taxi drivers and the management will rest with the members of such society, the statement said.

On Wednesday, Union Minister for Cooperation Amit Shah had told Lok Sabha that a 'Sahkar Taxi' on the lines of Ola and Uber will be rolled out in the near future. Two-wheelers, taxis, rickshaws and four-wheelers can register and the profit will go directly to the driver, Shah had said.

"The objective of this initiative is to ensure democratic management by active participation of all members and to ensure that maximum profit earned by such cooperative taxi society is distributed equitably among the taxi drivers who will be members of that society," the cooperative ministry's note stated. Such an initiative, the ministry said, will improve the income and working conditions for such taxi drivers and members of the cooperative society while providing better services to consumers.

The ministry said that the government has promoted and assisted startups and other enterprises in the past for equitable & inclusive growth of the nation. "India is home to over 8 lakh cooperative societies, serving nearly 30 crore members across 30 different sectors," it said.

Cooperation will bring change in the country



विश्लेषण

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक, 2025 पेश कर दिया और सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित भी कर दिया है। देश में निश्चय ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में गहरी सोच का अभाव था, स्वरोजगार और छोटी उद्यमिता के विकास में अरुचि थी। इससे न तो सामाजिक समावेशिता के लक्ष्य पूर्ण हो पा रहे थे और न ही नवाचार में हमारे युवाओं व वैज्ञानिकों के बीच सोच विकसित हो पा रही थी। भारत में नरेंद्र मोदी सरकार के बाद सहकारिता मंत्रालय की स्थापना एक दूरदर्शी लक्ष्य रहा है। भारत में सहकारिता में जनमानस की अपनी सहभागिता दिखती रही है।

देश में सहकारिता से आएगा बदलाव

भा रत में सहकारिता का यह स्वर्णिम काल है। इस समय देश के गृह मंत्री अमित शाह ने स्वयं सहकारिता आन्दोलन की बयार को तेज कर दिया है। देश में आजादी के बाद सहकारिता का लेकर किया जा रहा कार्य स्वर्णाश्रम में अंकित हो रहा है, ऐसा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात न होगी। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक, 2025 भी पेश कर दिया और सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। देश में निश्चय ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में गहरी सोच का अभाव था, स्वरोजगार और छोटी उद्यमिता के विकास में अरुचि थी। इससे न तो सामाजिक समাবেशिता के लक्ष्य पूर्ण हो पा रहे थे और न ही नवाचार में हमारे युवाओं व वैज्ञानिकों के बीच सोच के बाड़ सहकारिता में हो पा रही थी। भारत में नरेंद्र मोदी सरकार के बाद सहकारिता मंत्रालय की स्थापना एक दूरदर्शी लक्ष्य रहा है।

इस मंत्रालय की बागडोर सहकारिता में अभिरुचि रखने वाले नेता अमित शाह ने जब सम्माली तो उन्होंने कम समय में बहुत कुछ कर दिखाया जिससे आज भारत का आम आदमी लाभान्वित हो रहा है। वस्तुतः भारत में सहकारिता में जनमासिकी अपनी सहभागिता देखिती रही है। सहकारिता मंत्रालय बन जाने से इस क्षेत्र में फोकस होकर कार्य करने और उपलब्धियों को हासिल करने में बल मिला है। इससे भारत सरकार को बल मिला है और अच्छी बात यह है कि भारत के लोग अपने उद्यम, अपने श्रम और अपनी गरिमा को संयोजित व सुनिश्चित करने लगे हैं। लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी युनिवर्सिटी विधेयक, 2025 पेश करते हुए सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा भी कि सहकारिता एक ऐसा विषय है जो देश में हर परिवार को छूता है। हर गाँव में कोई न कोई ऐसी इकाई है जो सहकारिता के माध्यम से कृषि विकास, ग्रामीण विकास और स्वरोजगार के काम में जुटी हुई है और देश के विकास में योगदान करती है। आजादी के 75 वर्षों बाद आज देश को पहला सहकारिता विश्वविद्यालय मिल रहा है। इस विधेयक के पारित होने के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, स्वरोजगार और छोटी उद्यमिता का विकास होगा, सामाजिक समावेशिता बढ़ेगी और नवाचार तथा अनुसंधान में कई नए मानांक स्थापित करने के अवसर भी मिलेंगे। सबसे अहम बात जो अमित शाह ने कही, वह यह कि इस प्रकार पूरे देश को सहकारिता की भावना से युक्त और आधुनिक शिक्षा से लैस एक नया सहकारिता नवेलो मिलेगा।

भारतीय समाज में सहकारिता की यह अलख जगाने की इच्छाशक्ति निःसंदेह प्रशंसनीय है और अनुकरणीय

भी है। भारतीय जनमानस को स्वावलंबन देने व अपने संकल्प से देश को विकास पथ पर आगे ले जाने की दिशा में यह अमिट शाह का कार्य है। उनकी इस विधवालय को स्थापित करने के पीछे मांश बहुत पवित्र है, सबसे महत्वपूर्ण वह है। वह इस कोआपरेटिव क्षेत्र के विकास और विस्तारित करने की कोशिश में हैं। वह चाहते हैं कि प्रशिक्षित मानव संसाधन की जरूरत हमें पड़ेगी, उसकी भरपाई त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी से वह पूरा कर सकें। अमिता शाह ने उम्मीद ही नहीं विश्वास व्यक्त किया है कि सहकारी यूनिवर्सिटी बनने के बाद इसके डिप्लोमा और डिग्री धारकों को नौकरी



मिलेंगे। इस यूनिवर्सिटी से हम डोमेस्टिक के साथ ग्लोबल वैल्यू चैन में भी बड़ा योगदान करेंगे। न्यू एज कोऑपरेटिव कल्चर भी इस यूनिवर्सिटी से शुरू होगा। उनकी चिंता है कि देशभर में हजारों की संख्या में सहकारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान फैले हुए हैं, मगर इनके कोर्स में कोई मानकीकरण नहीं है। वह चाहते हैं कि इसे हम व्यवस्थित कर सकें। उन्होंने इसीलिए लोक सभा में विधेयक पेश करते हुए अपने जवाब में कहा कि हमने यूनिवर्सिटी बनने से पहले ही कोऑपरेटिव क्षेत्र की जरूरत को ध्यान में रखकर कोर्स डिजाइन का काम शुरू कर दिया है। यूनिवर्सिटी में डिग्री, डिप्लोमा कोर्स भी होंगे और पोपुलरी की डिग्री भी दी जाएगी। साथ ही सहकारी क्षेत्र में काम कर सभी मौजूदा कर्मचारियों के लिए अपेक्षावधि का सर्टिफिकेट कोर्स भी होगा।

सहकारिता क्षेत्र को समर्पित देश का पहला विश्वविद्यालय आजादी के 75 साल बाद बनेगा और सोचिए कि जब उससे हमारे देश की युवा आबादी प्रशिक्षित होगी तो सहकारिता को बढ़ावा देने वाले लोग, सहकारिता की सोच को आगे बढ़ाने वाले बौद्धिक वर्ग को हम तैयार करेंगे। गृह एवं लोक आजीविका मंत्री अमित शाह चाहते हैं कि प्रतिवर्ष लाखों युवा सहकारिता क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा

सर्टिफिकेट लकर सहकारी आंदोलन में सम्मिलित हों। शाह ने कहा भी कि वे 18 वर्ष की आयु से कोऑपरेटिव से जुड़े रहे हैं और इसकी खूबियाँ और कमियों का अनुभव किया है। मोदी जी एक समृद्ध भारत की नींव डाल रहे हैं और यह विधेयक इसमें मजबूत स्ट्रक्चर प्रदान करेगा। त्रिभुवन दास पटेल की सोच थी कि सहकारी क्षेत्र में मुनाफा हर गरीब महिला तक पहुंचे, इसलिए यह यूनिवर्सिटी उनके नाम पर रखने का प्रस्ताव किया गया है। इस विश्वविद्यालय के बनने से निश्चय ही अमित शाह के अपने सहकारिता सोच व स्वप्न को साकार होते हुए भारत के लोग देखेंगे और उससे लाभान्वित होंगे। दुनिया में बहु-क्षेत्रीय स्वनिर्भर सहकारिता संगठन आगे आकर कार्य कर रहे हैं। सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली शिक्षण व कौशल निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन विश्व भर में किया जा रहा है। जैसा कि केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस विधेयक के माध्यम से सहकारी सिद्धांतों और सहकारी गतिविधियों का विस्तार होगा, कोऑपरेटिव क्षेत्र को नई प्रोवोचिंगी का फायदा होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। साथ ही अनुसंधान और नवाचारी भी बढ़ेंगे और जमीनी स्तर पर कोऑपरेटिव क्षेत्र मजबूत भी होगा। त्रिभुवन दास जैसे महान व्यक्ति के नाम से जुड़े होने के कारण यह सहकारी यूनिवर्सिटी उच्च कोटि की यूनिवर्सिटी सिद्ध होगी। यह देश में बहुत अच्छे सहकारिता कर्मों देने का काम करेगी। यह उनका स्वाभाविक इच्छाशक्ति और अपनी आत्मशक्ति का प्रतिफल है। निःसंदेह अब त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से सहकारी क्षेत्र को संगठनों की कार्यक्षमता में सुधार, प्रशिक्षित मानव संसाधनों से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल नवाचारी के तहत सहकारी लेफ्टफार्म पर अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर सहकारी संस्थानों का निर्माण और नई फंडिंग योजनाओं के विकास के लिए वित्तीय रणनीतियों का सुजन होगा तो इससे देश ही विकास करेगा। अमित शाह ने अपने कम समय में जो प्रतिष्ठित अवदान विश्वविद्यालय के रूप में दिया है, उसका अभिन्नन्दन किया जाना चाहिए। यह सहकारिता के लिए नए नैरेटिव की स्थापना है। यह उनका भारत निर्माण की दिशा में किया जा रहा सदृशयास है। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक, 2025 भले ही अभी शुरू हो रहा है, लेकिन अपने वाले 2047 तक यह विश्वविद्यालय लाखों युवा सहकारी पैरोकारों को तैयार कर चुका होगा।

(लेखक राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में चेयर प्रोफेसर हैं, ये उनके अपने विचार हैं।
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।
